

खुशखबरी | यमुना आथारिटी अब नए सिरे से फिल्म सिटी में इच्छुक निवेशकों से कर रही संपर्क, जल्द नया बिड डाक्यूमेंट पेश होगा

यूपी की फिल्म सिटी के लिए आई फॉकस व यूनिवर्सल

■ अजित खरे

लखनऊ। यूपी के मेगा प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के लिए अब अमेरिकी कंपनियां आगे आई हैं। न्यूयार्क की 20 सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो व कैलिफोर्निया स्थित यूनिवर्सल स्टूडियो ने यमुना आथारिटी द्वारा विकसित की जाने वाली फिल्म सिटी में रुचि दिखाई है। यही नहीं दक्षिण भारत के दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक राजामौलि ने भी यहां स्टूडियो खोलने की इच्छा जताई है। ट्यूलिप फिल्म कंपनी भी यहां निवेश के लिए तैयार है। इसके अलावा प्रसिद्ध कलाकार रजनीकांत भी यहां दम प्रोजेक्ट के लिए रवासे उत्सुक

बताए जाते हैं।

इस फिल्म सिटी के अब तक दो बार टेंडर निरस्त होने के बाद अब नए सिरे से बड़े देशी विदेशी स्टूडियो या कंपनियां इस प्रोजेक्ट के लिए आगे आ रही हैं। निवेशक व फिल्म कंपनियां ज्यादा रियायतों की उम्मीद में हैं। अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने नए सिरे से हालीबुड, बालीबुड व दक्षिण भारत के निर्माता कंपनियों से संपर्क साधा और ज्यादा सहूलियतों के साथ निवेश का प्रस्ताव दिया। इस पर इन कंपनियों व निर्माता निर्देशकों ने यहां जमीन लेकर स्टूडियो बनाने का संकेत दिया है।

अब तीस चालों में होगा निवास-

नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी की खास-खास बातें

- यमुना आथारिटी के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी के लिए 780 एकड़ जमीन औद्योगिक व 220 एकड़ जमीन व्यवसायिक उपयोग के लिए
- यहां 6 पांच फिल्म शूट स्थल, 5 मीडिया व फिल्म इंडरस्ट्री कार्यालय, चार रिटेल हब, एक थीम पार्क, एक फिल्म व

पोर्ट प्रोडक्शन सुविधा केंद्र बनना है।

- इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 7210 करोड़ रुपये है।
- 370 करोड़ हॉस्पिटेलिटी पर, 359.63 करोड़ फिल्म सिटी पर, स्टूडियो पर 301 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अब एक साथ 1000 एकड़ में एक साथ फिल्म सिटी बनाने के बजाए, पहले 250 एकड़ जमीन पर काम होगा। यहां सारी सुविधाएं विकसित कर फिल्म कंपनियों को जमीन आवंटित की जाएगी। दूसरे चालों में 350 एकड़ व तीसरे चालों में 400 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी से जुड़ी सारे निर्माण व सुविधाएं विकसित होंगी। निवेशकों की मांग थी कि रेवन्यू शेयरिंग फार्मूला लागू किया जाए यादी मराए में कंपनी निश्चित

निर्माताओं को खुद से डिजाइनिंग की छूट

निर्माताओं को अपने हिसाब से डिजाइनिंग की छूट होगी। यह बदलाव निर्माताओं से मिले फीडबैक के आधार पर लिए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास विभाग जल्द इस मसीदे को अंतिम रूप देकर निवेशकों के सामने रखेगा।

हिस्सा सरकार को देगी। अभी तक मौजूदा प्रस्ताव में उन्हें हर साल 25 करोड़ रुपये प्रीमियम कुछ शर्तों के साथ देना था। अब इसमें कुछ बदलाव कर नए बिड डाक्यूमेंट में शामिल किया जा रहा है।